प्रेस नोट

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

वर्तमान सरकार के 09 माह कार्यकाल पूर्ण होने के दृष्टिगत विभाग द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय एवं कराये गये उल्लेखनीय कार्य

वर्तमान मुख्यमंत्री के 9 माह के कार्यकाल के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा लिए गए प्रमुख नीतिगत फैसले जिनसे सिंचाई विभाग का चहुमुखी विकास दिखाई देने लगा है। योगी सरकार का आम आदमी केन्द्रित दृष्टिकोण साफ दिखाई दे रहा है, कृषि को बढ़ावा देना एवं सिंचाई क्षेत्र में सुधार करना। गंगा, रामगंगा, घाघरा, सरयू, गण्डक एवं राप्ती इत्यादि नदियों की बाढ़ सुरक्षा एवं घाट निर्माण व तीर्थ स्थलों की पवित्रता के कार्य तेजी से कराये जा रहे हैं। जनपद–बरेली में अरिल नदी व जनपद–बदायूँ की सोंत (स्रोत) नदी व जनपद–पीलीभीत से निकली गोमती नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य चिन्हित किया गया है।

1– सरकार ने नदियों के संरक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है जिसके द्वारा प्रत्येक जनपद में एक नदी या जल स्रोत के पुर्नजीवीकरण के चलाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य मनरेगा तथा जन सहभागिता के द्वारा कराया जाएगा। वहॉ के मा0 विधायकगण, मा0 सांसद तथा क्षेत्र के प्रभावी लोग भी इसमें अपना श्रमदान करें यथा सम्भव सहयोग लिया जाएगा।

2–किसानों की आय दोगुनी करने मा मा0 प्रधान मंत्री जी का जो संकल्प है **'वन ड्राप मोर काप'** को सफल बनाने हेतु उत्तर प्रदेश के **33 हजार राजकीय नलकूपों पर ड्रिप** स्प्रिंकलर लगाने का निर्णय लिया गया है और माडल के रूप में प्रत्येक नलकूप पर एक हेक्टेयर जमीन इस योजना से सिंचित की जायेगी। 250 लिफ्ट कैनाल पर ड्रिप इरीगेशन का प्रबन्ध किया जायेगा।

3– मेरे द्वारा सिंचाई मंत्री बनने के बाद कार्य में शिथिलता में दोषी तथा विभिन्न जॉचों में दोषी पाये गये विभाग के अभियन्ताओं के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की गयी तथा उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान भी किया गया ।

4– नहरों की सिल्ट सफाई वर्ष में एक ही बार कराये जाने तथा नहरों की सिल्ट सफाई के कार्यो की निगरानी ड्रोन कैमरे से कराये जाने के निर्देश जारी किये गये ।

5– नहरों की सिल्ट सफाई के कार्यो के उपरान्त नहरों की उचित ड्रेसिंग एवं जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद ही सिल्ट सफाई के कार्यो का भुगतान करने के निर्देश जारी किये गये ।

6– रबी–1425 फसली वर्ष 2017–18 में विभागीय मद के अन्तर्गत कुल 16,818.87 कि0मी0 लक्ष्य के सापेक्ष 14,264.89 कि0मी0 नहरों की सिल्ट सफाई करायी गयी है, जो लक्ष्य का 85 प्रतिशत है।

7– प्रथम बार सिंचाई विभाग के (शीर्षस्थ अधिकारी) प्रमुख अभियन्ताओं को नहरों में चल रहे सिल्ट सफाई के कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश जारी किये गये ।

8– रामगंगा बांध कालागढ़ मेंटनल टी–1 एवं टी–2 में गत वर्षो से खराब वाटर फ्लाई वाल्ब एवं सिलेण्ड्रीकल गेट की मरम्मत कराई गयी एवं बांध के 353.00 मीटर लेविल तक पानी भरा जा चुका है । बांध का एफ0आर0एल0 365.30 मीटर है । जनपद पौड़ी में रामगंगा बांध एवं सैडिल बांध के गेटों को पूर्णतः स्वचालित कराया गया ।

...2–

Scanned by CamScanner

9– विभाग में चालू नहर प्रणाली सृजित सिंचन क्षमता व प्राप्त सिंचन क्षमता के गैप को कम करने हेतु माइक्रो, ड्रिप/स्प्रिंगलर सिंचाई को प्रोत्साहन देना तथा गूलों आदि के विकास कार्य हेतु योजनाएं बनाई गयी है ।

10–पंजीकृत दागी फर्मो एवं अपराधिक प्रवृत्ति के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त कर अच्छी, साफ–सुथरी छवि की संस्थाओं को मौका दिया जाना तथा विभाग में क्रय/आपूर्ति एवं निर्माण आदि कार्यो में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

11–केन–बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है ।

12–प्रदेश को हर खेत में पानी पहुॅचाने के लिये रु0–20000 करोड़ के सिंचाई फण्ड की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

13–''वन ड्राप मोर क्राप'' के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय नलकूपों पर ड्रिप स्प्रिंगलर एवं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्थापित कराये जाने हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में क्रमशः 20–20 राजकीय नलकूपों पर उक्त सिस्टम स्थापित किये जाने का निर्णय लिया जा रहा है ।

14–वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत नवनिर्मित राजकीय नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु प्रेषित 196.00 अदद बी0 एण्ड एल0 फार्म के विरूद्ध 168.00 अदद राजकीय नलकूपों का ऊर्जीकरण करा दिया गया है ।

15–सिंचाई विभाग के अधिकारियों को शनिवार के दिन भी कार्यालय खोलने के निर्देश जारी ।

16–उत्तर प्रदेश में सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत् जल उपभोक्ता समितियों का चुनाव कराया जायेगा जिसमें **कुलाबा समिति, अल्पिका समिति और राजवाहा समिति** का चुनाव कराया जायेगा। मतदाता सूची 28–2–2018 तक बन जायेगी और जून, 2018 तक चुनाव करा दिये जायेंगे। जल उपभोक्ता समितियों का गठन हो जाने से पानी का अपव्यय बचेगा और किसानों की सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी।

17–ड्रिप इरीगेशन के द्वारा किसानों की फसल का उत्पादन अधिक हो जायेगा, इसके लिये योगी सरकार ने प्रोत्साहन देने का काम किया है। सीमान्त और लघु सीमान्त किसानों **को 90 प्रतिशत** का अनुदान एवं सभी **किसानों को 80 प्रतिशत** का अनुदान देने का काम किया है जिससे किसानों की आय दो गुनी होगी।

18–उत्तर प्रदेश में चल रही 04 राष्ट्रीय परियोजनाएं जिसमें 1–मध्य गंगा नहर परियोजना 2–सरयू नहर परियोजना 3–बाण सागर परियोजना 4–अर्जुन सहायक परियोजना। पिछली सरकारों ने इन परियोजनाओं को पूरा नहीं किया। योगी सरकार इन चारों राष्ट्रीय परियोजनाओं को पूरा करेगी, इसके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

———————

Scanned by CamScanner